

NATIONAL FEDERATION OF INFORMATION COMMISSIONS IN INDIA Minutes of 14th Annual General Body Meeting held on April 8th, 2025 At Guwahati (Assam)

Chief Guest: His Excellency, Shri Lakshman Prasad Acharya, Governor of Assam Participants:

Board of Governors:

- Shri Heeralal Samariya, President NFICI & Chief Information Commissioner, CIC New Delhi.
- Shri Tripurari Sharan, Vice President, NFICI & Chief Information Commissioner, SIC Bihar.
- Shri R. Mahaboob Basha, Chief Information Commissioner, SIC Andhra Pradesh.
- Shri Konjam Radhashyam Singh, Chief Information Commissioner, SIC Manipur.
- Dr. Pradeep Vyas, Chief Information Commissioner (I/c), SIC Maharashtra.
- Shri Susant Kumar Mohanty, Chief Information Commissioner (I/c), SIC Odisha
- Shri Kuber Bhandari, Information Commissioner, SIC Sikkim

Members Present:

- Shri Bhaskar Jyoti Mahanta, Chief Information Commissioner, SIC Assam
- Maj. Gen. Jarken Gamlin, Chief Information Commissioner, SIC Arunachal Pradesh
- Dr. Subhashchandra Soni, Chief Information Commissioner, SIC Gujarat.
- Shri Arvind Kumar H. Nair, Chief Information Commissioner, SIC Goa
- Shri Ashit Mohan Prasad, Chief Information Commissioner, SIC Karnataka
- Shri Md. Shakeel Akhter, Chief Information Commissioner, SIC Tamil Nadu
- Shri Virendra, Chief Information Commissioner, SIC West Bengal
- Shri Narendra Kumar Shukla, Information Commissioner, SIC Chhattisgarh
- Dr. Sonichan P. Joseph, Information Commissioner, SIC Kerala
- Smt. Ripnar Lyngdoh, Chief Information Commissioner (I/c), SIC Meghalaya
- Shri Mangjangam Touthang, Information Commissioner, SIC Mizoram
- Shri Mahendra Kumar Parakh, Information Commissioner, SIC Rajasthan.

Special Invitee:

- Shri Vijay Yadav, Chief Information Commissioner, SIC Madhya Pradesh
- Shri Binoy Shankar Mishra, Chief Information Commissioner, SIC Tripura
- Dr. Raj Kumar Vishwakarma, Chief Information Commissioner, SIC Uttar Pradesh

Also Present:

• Dr. Reep Hazarika, Information Commissioner, SIC Assam.

NFICI's officers:

- Brig Vipin Chakrawarti, Honorary Secretary, NFICI, New Delhi
- Shri Sarvottam Kumar Rana, Executive Secretary, NFICI, New Delhi.

Shri Heeralal Samariya, Chief Information Commissioner, Central Information Commission and President of NFICI, commenced the session with a warm welcome and thanked the Chief Guest, His Excellency Shri Lakshman Prasad Acharya, Governor of Assam, for taking out time to address the 32nd Board of Governors and 14th Annual General Body Meetings of National Federation of Information Commissions in India (NFICI). He also welcomed and thanked all the participants.

In his welcome address, Shri Samariya said, "I welcome you all on the occasion of the 32nd Board of Governors and the 14th Annual General Body meetings of NFICI. It is an honour for all of us that His Excellency, Shri Lakshman Prasad Acharya, Governor of Assam, is with us today. Pointing towards the HE Governor, Sir we are grateful to you for you taking out time out of your busy schedule.

It gives me immense pleasure to inform you that NFICI has become a great platform for sharing best practises, promoting awareness and improving the performance of Central and State Information Commissions. It also facilitates coordination among Central and State Information Commissions and ensures a uniform approach in the implementation of the RTI Act. This landmark law has been enacted to usher in a new era of transparency and accountability aimed at shedding light on the decision-making process, holding officials accountable for their actions and rooting out corruption"

He further asserted, "Our collective efforts have resulted in significant achievements in the effective implementation of the RTI Act across the country. Since the Indian Constitution provides

for a democratic republic and democracy requires an informed citizenry, NFICI has been organising public awareness campaigns not only in urban areas but also in remote areas. It promotes knowledge and encourages transparency and accountability initiatives. In addition, NFICI has disbursed grants to State Information Commissions to enable them to undertake initiatives to promote awareness and educate citizens about the RTI Act by organising seminars, campaigns and other outreach programmes.

I am pleased to highlight the pivotal role of NFICI in facilitating the hybrid mode of hearing in the Central Information Commission as well as various State Information Commissions. This innovative initiative has ensured that citizens have uninterrupted access to information and justice and has improved disposal rate of second appeals and complaints despite the challenges posed by the pandemic. This approach, adopted in all State Information Commissions (SICs) in India, has enabled speedy disposal of cases while allowing complainants to attend hearings from a location of their choice. This initiative demonstrates the commitment to effective implementation of the RTI Act. The NFICI, in consultation with the Central Information Commission, has made available the source code of the AppComs application so that the State Information Commissions can adopt uniform processes and ensure smooth hybrid operations, thereby improving overall efficiency and consistency.

Sir, we assure you that we are all committed to the implementation of the RTI Act in its entirety and to the expeditious disposal of 2nd Appeals / Complaints so that the appellants and complainants can get the information expeditiously.

While concluding, Shri Samariya ji once again expressed his pleasure and warmly welcomed all the distinguished guests and especially His Excellency, Shri Lakshman Prasad Acharya, Governor of Assam and said that their presence was a great honour for all of us.

His Excellency Shri Lakshman Prasad Acharya, Governor of Assam, while addressing the 32nd Board of Governors and 14th Annual General Body meetings of National Federation of Information Commissions in India (NFICI) extended warm welcome and greetings to all the participants. In his speech, he said, "नमस्कार!

भारतीय राष्ट्रीय सूचना आयोग संघ की 32वीं गवर्निंग बोर्ड एवं 14वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर उपस्थित;

- भारत के मुख्य सूचना आयुक्त एवं फेडरेशन के अध्यक्ष श्री हीरालाल समारिया जी,
- फेडरेशन के उपाध्यक्ष एवं बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त श्री त्रिपुरारी शरण जी,
- असम के मुख्य सूचना आयुक्त श्री भास्कर ज्योति महंत जी,
- विभिन्न राज्यों के सूचना आयुक्त गण,
- राष्ट्रीय सूचना आयोग संघ के सदस्य गण,
- मीडिया के हमारे मित्रों,
- देवियों और सज्जनों,

सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। यह आयोजन केवल फेडरेशन की औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र मे पारदर्शिता बनाए रखने की संस्कृति का उत्सव है।

हमारे भारतीय समाज में सूचना का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रहा है। चाहे रामायण में हनुमान जी द्वारा प्रभु श्री राम के आगमन की सूचना भरत को देना हो, चाहे महाभारत में संजय द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रसंग सुनाना हो, चाहे देविष नारद द्वारा तीनों लोकों का वर्णन करना हो, सूचना हर काल में एक विशेष महत्व रखता आया है। सूचना केवल एक संदेश नहीं होती, बल्कि यह एक जीवनरेखा होती है।

स्चना का अधिकार अधिनियम, 2005, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। मैं समझता हूं कि यह अधिनियम मात्र एक अधिकार नहीं, बल्कि यह वह सेतु है, जो आम नागरिक और सरकार के बीच की दूरी को कम करता है। यह शासन में आम नागरिकों की भागीदारी का सशक्त माध्यम है। यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को प्रशासन से प्रश्न पूछने तथा जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम उस सिद्धांत को सशक्त करता है कि - "जनता ही शासन की असली मालिक है" और जब मालिक जागरुक हो, तो व्यवस्था सजग और संवेदनशील बनती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम ने हमारे देश में न केवल पारदर्शिता बढ़ाई है, बिल्क इसने अष्टाचार पर लगाम, प्रशासनिक जवाबदेही और सेवा वितरण में सुधार लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित समुदायों के लिए यह अधिनियम एक वरदान है, जिसने उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की ताकत दी है। इस अधिनियम ने सरकारी प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। इसने सरकारी संगठनों में उत्तरदायित्व और व्यावसायिकता की संस्कृति को बढ़ावा दिया।



हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित शासन केंद्र और राज्य सरकार के गवर्नेंस मॉडल का आधार बन चुका है। प्रधानमंत्री जी के Minimum Government, Maximum Governance के विजन के अनुरुप यह शासन मॉडल न केवल प्रसाशनिक प्रक्रियाओं को सरल, तेज़ और प्रभावी बना रहा है, बल्कि जनसामान्य की भागीदारी को भी सशक्त कर रहा है।

सरकार ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित की है। डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और आयुष्मान भारत जैसी पहलें इसी सोच का प्रमाण है, जहाँ हर नीति का का केंद्र बिंदु "जनता जनार्दन" रही है। इसके परिणामस्वरूप, जनता का विश्वास शासन व्यवस्था में बढ़ा है।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय संसद द्वारा पारित यह अधिनियम दुनिया के अन्य देशों के लिए एक आदर्श बन गया। इसकी सफलता ने पारदर्शिता, जवाबदेही, और नागरिक सशक्तिकरण को प्रेरित किया, जिससे अनेकदेशों ने इसी तरह के कानून बनाए और एक वैश्विक पारदर्शिता आंदोलन की शुरुआत हुई।

आज का युग डिजिटल भारत का युग है। जब सूचनाएं तीव्र गित से प्रवाहित होती हैं, तब पारदर्शिता और जवाबदेही पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हमें सूचना के अधिकार को डिजिटल रुप से और अधिक सुलभ, सहज एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयास तेज करने होंगे।

यह आवश्यक है की हम आरटीआई को केवल कागजों में सीमित न रखें, बल्कि उसे जनमानस के व्यवहार में शामिल करें । इसके लिए व्यापक जन-जागरुकता की आवश्यक है- स्कूलों में, पंचायतों में, नगर निकायों में, हर गली -मोहल्ले में। पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए । स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों को इससे जोड़ना चाहिए।

हमें सूचना के अधिकार को अगली पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक बनाना होगा। इसके लिए हम दूरदर्शिता के साथ नवाचारों को अपनाना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सूचना प्रणाली को और स्मार्ट और सुलभ बनाया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम को निजता (privacy), डेटा सुरक्षा और फेक न्यूज जैसी चुनौतियों के अनुरूप अद्यतन भी करना होगा।

W

यह फेडरेशन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना आयोगों का साझा मंच है। आरटीआई को आगे बढ़ाने में इस फेडरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे खुशी है कि फेडरेशन आरटीआई को एक सशक्त जनांदोलन बनाने के लिए प्रयासरत है।

एक सशक्त लोकतंत्र वह नहीं होता, जहाँ केवल सरकार मजबूत हो, बल्कि जहाँ नागरिक सशक्त और जागरूक हो। आरटीआई अधिनियम हमें यही जागरूकता प्रदान करता है। यह हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, साहस देता है, विश्वास देता है, और उत्तरदयुक्त उत्तरदायित्व की भावना भी जगाता है।

मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि -

"जब सूचना सुलभ होती है, तब समाज सुरक्षित होता है; जब सूचना रोकी जाती है, तब लोकतंत्र कमजोर होता है।"

आइए, हम सब मिलकर इस अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली, जीवंत और सर्वसुलभ बनाने का संकल्प लें।

मैं इस यात्रा में योगदान देने वाले सूचना आयुक्तों, आयोगों, नागरिक समाज संगठनों, और जागरूक नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ। मैं पुनः भारतीय राष्ट्रीय सूचना आयोग संघ को हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी गुवाहाटी में इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बधाई देता हूँ तथा इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद।

जय हिंद।"

Shri Bhaskar Jyoti Mahanta, Chief Information Commissioner, Assam while delivering vote of thanks expressed his gratitude towards Chief Guest, His Excellency Shri Lakshman Prasad Acharya, Governor of Assam for his presence in the inaugural ceremony. He also extended warm welcome to all the dignitaries present at the function. Shri Mahanta also thanked the Hon'ble President, NFICI, Shri Heeralal Samariya for giving State Information Commission Assam an opportunity to organise such an important meeting of NFICI in the State Assam.

All the members assembled for the next session after the tea break and departure of Chief Guest.

CIC's of all the States put across their views and give presentation on the functioning of State Information Commissions and implementation of RTI Act in respective States.

Page 6 of 13

Thereafter, Shri Heeralal Samariya, President of NFICI, asked Shri Sarvottam Rana, Executive Secretary, to present the agenda items of the 14th Annual General Meeting.

On behalf of the President, NFICI Shri Sarvottam Rana, Executive Secretary, NFICI welcomed all the Hon'ble members present to the 14th Annual General Body and 32nd Board of Governors meetings of NFICI.

Before beginning the discussion on the agenda points, Shri Rana introduced the special guests; Dr. Raj Kumar Vishwakarma ji, Hon'ble CIC Uttar Pradesh, Shri Vijay Yadav ji, Hon'ble CIC Madhya Pradesh and Shri Binoy Shankar Mishra ji, Hon'ble CIC Tripura to all the members and extended a warm welcome to them.

Shri Rana thanked all the special guests for giving their valuable time and said that surely they will find it a best platform for sharing of knowledge and best practices. He informed all the members, that the State Information Commissions of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Tripura have not yet officially joined the Federation, but we are looking forward for them becoming members of the Federation very soon. All the special guests were once again thanked for attending the meetings of NFICI on behalf of the Federation.

Thereafter, Shri Rana congratulated and welcomed to General. Jarken Gamlin, CIC Arunachal Pradesh, Shri Arvind Kumar H. Nair, CIC Goa, Shri Ashit Mohan Prasad, CIC Karnataka, Smt. Ripnar Lyngdoh, CIC (I/c) Meghalaya and Shri Susant Kumar Mohanty, CIC (I/c) Odisha as they were attending the NFICI meetings for the first time after becoming Chiefs of their respective State Information Commissions.

The Executive Secretary then proceeded with the following agenda items with the permission of the President and members:

1. Confirmation of Minutes of last Meeting.

The 13th Annual General Body meeting was held on 02 Aug 2024 at CIC Bhawan, New Delhi. The members were asked to confirm the minutes. The members of the Federation unanimously confirmed the minutes of the meeting.

2. Election of members for Board of Governors.

Executive Secretary apprised the Federation that as per existing policy, Members of Board of Governors are elected for a tenure of two years. State Information commissions Uttarakhand,

Maharashtra, Manipur and Odisha have completed their tenure on 17.11.2024. The Executive Secretary requested the members of the Federation to consider electing new BOG members from their respective zones.

The members unanimously elected the following members as Board of Governors for a term of two years from 08.04.2025:

S.No.	Elected Member for BOG	Zone	In place of		
1.	Punjab State Information Commission	II	Uttarakhand State Information Commission		
2.	Rajasthan State Information Commission	IV	Maharashtra State Information Commission		
3.	Meghalaya State Information Commission	VI	Manipur State Information Commission		
4.	West Bengal State Information Commission	VII	Odisha State Information Commission		

3. Status of NFICI's Current Accounts and Fixed Deposits.

The Executive Secretary informed the members of the Federation that the NFICI's current account and fixed deposits are being maintained at State Bank of India, NIHFW Munirka Branch New Delhi. A sum of Rs. 8,64,301/- was existing balance in the current account as on 31.03.2025.

In addition to this, the Federation had 12 Fixed Deposits also which were amounting to Rs. 1,77,58,278/- (principal amount) as on 31.03.2025. These are also being maintained in the same branch.

4. Status of Annual membership fee for the FY 2024-25.

The members were apprised about the status of NFICI's Annual Membership Fee up to the financial year 2024-25. It was informed that in the 13th Annual General Body meeting held on 02 Aug, 2024 at New Delhi, all the member Information Commissions were requested to deposit the Annual Membership Fee for the financial year 2024-25. All the member Information Commissions except Karnataka and Telangana have deposited Annual Membership Fee for the FY 2024-25. The Board of Governors directed to request State Information Commissions Karnataka and Telangana to deposit outstanding Annual Membership Fee for the financial year 2024-25.

5. Status of release of 4th Grant of Rs. 4.00 Lakhs to member Information Commissions:

It was informed to the members that in the 13th Annual General Body meeting held on 02 Aug, 2024 at New Delhi, it was decided that 4th Grant of NFICI for Rs. 4.00 lakh should be released to the eligible member Information Commissions. Accordingly, 4th grant has been released to the following State Information Commissions:

S.No.	State Information	Amt. Released	Cheque No. &	
	Commission	(in Lakhs)	Date	
1	Gujarat	1.00	094473	
1.		4.00	27.09.2024	
2	Mizoram	4.00	094471	
2.			27.09.2024	
2	Nagaland	4.00	094472	
3.			27.09.2024	
1	Odisha	4.00	094470	
4.			27.09.2024	
5	Daiasthan	4.00	094468	
5.	Rajasthan	4.00	27.09.2024	
6	Sikkim	4.00	094479	
6.			27.09.2024	

6. Consideration on release of the 4th grant to reaming eligible member Information Commissions:

Member of the Federation were informed that the following Member Commissions have submitted the Utilisation Certificates and supporting vouchers for all the First, Second and the Third Grants. Now, the Fourth Grant can be released to the following State Information Commissions.

S.No.	State Information Commission	Eligible for grant	Remarks
1.	Arunachal Pradesh	4 th	
2.	Assam	4 th	
3.	Himachal Pradesh	4 th	
4.	Karnataka	4 th	Rs.3,98,132/- UC & Voucher are received from 3rd grant. Balance Rs. 1,868/- to be carried forward with 4 th grant.
5.	Meghalaya	4 th	7
6.	Manipur	4 th	
7.	Tamil Nadu	4 th	Rs.3,95,293/- UC & Voucher are received from 3rd grant. Balance Rs. 4,707/- to be carried forward with 4 th grant.
8.	Uttarakhand	4 th	ıd

The matter to release 4th grant of Rs. 4.00 lac was discussed in detail. The Board of Governors decided to release the 4th grant to those member Information Commissions who are eligible for it and express their willingness for its utilisation.

The members had a deliberated discussion and decided that the Federation should increase the Annual Membership Fee from Rs. 1 lac to Rs. 1.5 lac and grants being released by the NFICI should be increased from Rs. 4 lac to Rs. 5 lac. All the members agreed to this proposal unanimously, and it was decided that Annual Membership Fee to be increased from the FY 2025-26 and increased rate of release of grant should be applicable from the 5th grant. Members also agreed to amend the By-laws accordingly.

7. Raising of demand for Annual Membership Fee for the FY 2025-26.

The Executive Secretary apprised the members that Annual Membership fee for the FY 2025-26 has become due. All the members present decided unanimously that all the members be requested to deposit Annual Membership fee @ Rs 1.5 lac for the FY 2025-26 at the earliest.

8. Status of UC and vouchers from members Information Commissions.

The Executive Secretary apprised that the Federation releases grants to its Member Information Commissions to undertake schemes as per the guidelines for utilization of funds/grants. Member Information Commissions are required to submit verified utilization certificates and supporting vouchers to the office of NFICI. The details of release of grants, receipt of utilization certificates and supporting vouchers from member Information Commissions was apprised to members of the Federation as under:-

	State	1st Grant	2 rd Grant	3 rd Grant	4 th Grant	Remarks
S.No.	Information Commission	Status of UC & Vouchers	Status of UC & Vouchers	Status of UC & Vouchers	Status of UC & Vouchers	
1	Andhra Pradesh	Received	Received	Pending		
2	Arunachal Pradesh	Received	Received	Received		
3	Assam	Received	Received	Received	8	
4	Bihar	Pending	-	1-		
5	Chhattisgarh	Received	UC & Vouchers of Rs. 3,62,890/- have been received in r/o 2nd Grant.	Pending		

6	CIC, Delhi	-	_	-		CIC Delhi has not availed any Grant.
7	Gujarat	Received	Received	Received	Received	UC & Vouchers for Rs. 4.00 lakh received by mail on 28.03.2025
8	Goa	NA	Received	Pending		
9	Himachal Pradesh	Received	Received	Received		
10	Haryana	Received	Pending	-		
11	Jharkhand	UC and voucher of Rs. 1,95,390/- have been received in r/o 1st grant.	-	-		Jharkhand SIC has refunded the unutilized balance of Rs 4,610/- from the first grant.
12	Kerala	Received	Received	Pending		
13	Karnataka	Received	Received	UC & Vhrs of Rs. 3,98,132/- have been received.		
. 14	Maharashtra	Received	Received	Pending		1911
15	Meghalaya	Received	Received	Received		
16	Manipur	Received	Received	Received		
17	Mizoram	Received	Received	Received	Pending	
18	Nagaland	Received	Received	Received	Pending	P
19	Odisha	Received	Received	Received	Pending	
20	Punjab	Received	Received	Pending		
21	Rajasthan	Received	Received	Received	Pending	
22	Sikkim	Received	Received	Received	Pending	
23	Tamil Nadu	Received	Rs. 3,94,935/- UC & Vouchers have been submitted in r/o 2 nd Grant	Received Rs. 3,95,293/- UC & Voucher have been received by letter dt. 07.08.2024		

24	Telangana	-	-	-	
25	Uttarakhand	Received	Received	Received	
26	West Bengal	Received	Received	Pending	

The Executive Secretary proposed that we may approach those Member Information Commissions who have not yet submitted their outstanding Utilization Certificates and Supporting Vouchers for the grants released to them. All the members agreed to this unanimously.

9. Status of receipt of important and landmark decisions from member Information Commissions.

The Executive Secretary informed that an Editorial Board was constituted for selection of landmark and important decisions issued by the members Information Commissions to be notified through Annual Journal. The following are the members of the Editorial Board:-

- 1) Shri Virendra, Chief Information Commissioner, West Bengal; Chief Editor
- 2) Shri M.L. Lather, Chief Information Commissioner, Rajasthan;
- 3) Shri V Hari Nair, Chief Information Commissioner, Kerala;
- 4) Dr. Pradeep Vyas, Chief Information Commissioner, Maharashtra;
- 5) Shri K. Radhashyam Singh, Chief Information Commissioner, Manipur;
- 6) Dr. Subhashchandra Soni, Chief Information Commissioner, Gujarat.

In pursuance of the above decision, the Federation had requested all the Member Information Commissions to submit their important and landmark decision upto the year of 2024.

It was apprised that the Federation has received 167 decisions for 13 Member Information Commissions. 6 Members Commissions have submitted 'Nil' report.

The members present in the meeting directed the Executive Secretary to approach all the Member Commissions to submit their decisions on Priority so that the journal can be published.

10. Agenda points received from following State Information Commissions:

(1) Goa State Information Commission.

- (i) Mechanism to ensure compliance of FAA's order.
- (ii) Engagement of Advocates from Government panel.

H

(2) Andhra Pradesh State Information Commission

- (i) Implementation of directions of Hon'ble Supreme court of India in its order dated 09.010.2023 on the W.P. (C) No. 360 of 2021 titled Kishan Chand Jain Vs UOI case.
- (ii) Welfare of the out-sourcing employees working in the Information Commissions.
- (iii) Assigning a regular employee in each office to handle applications appeals and complaints related to RTI Act 2005.
- (iv) Proposal of Pension to the State Chief Information Commissioners and Information Commissioners.

The detailed deliberation was made on the above agenda points by all the members of the Federation.

11. Any other item with the permission of the Chair.

(i) The Executive Secretary apprised the members that the Federation releases a sum of Rs. 8 lac or total expenditure whichever is less for hosting the Special/Annual General Meeting of NFICI. However, the State Information Commissions hosting the meetings find it difficult to organize the meetings, being Rs 8 lac inadequate. He requested the members to consider increasing the amount suitably. Members had a detailed discussion on this issue and finally decided that a sum of Rs 10 lac or the actual expenditure, whichever is less, should be released to the member information hosting the meeting. It was also discussed and decided that the increased amount should be applicable from the 14th Annual General Body Meetings organized by the State Information Commission, Assam.

There being no other point, Brig. Vipin Chakrawarti, Honorary Secretary, NFICI, delivered a vote of thanks, and the meeting was concluded.

(Heeralal Samariya)

President, NFICI